हिन्दुस्तान दि. 06-09-13

अब बीडीओ की जगह लेंगे ग्रामीण विकास पदाधिकारी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में प्रखंड प्रशासन की कमान संभालने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के स्थान पर जल्द ही ग्रामीण विकास पदाधिकारी (आरडीओ) बहाल होंगे। राज्य के सभी प्रखंडों में एक साथ पहली बार रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर को तैनात करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने अलग से संवर्ग तैयार किया है। इस संवर्ग में इस बार हुई बीपीएससी की परीक्षा से पहली बार 534 पदाधिकारियों की बहाली हुई है। इसकी सूची जल्द ही बीपीएससी विभाग को सौंपने वाला है।

ग्रामीण विकास विभाग में इनकी सूची आने के बाद विभाग इनका प्रशिक्षण शुरू कराएगा। इन आरडीओ को बिपार्ट में तीन महीने का संस्थानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 60-60 पदाधिकारियों का बैच बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें जिला, कोषागार, अनुमंडल का प्रशिक्षण देकर तमाम विभागीय कार्यों की बारीकियां बतायी जाएगी। इन्हें प्रखंडों में तैनात करके फील्ड प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में मनरेगा, इंदिरा आवास समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उदाहरणों से रूबरू कराने के लिए इन्हें अन्य राज्यों का दौरा कराया जाएगा।

इन सभी तरह के प्रशिक्षण की कुल अवधि एक वर्ष होगी। विभाग ने डिप्टी कलेक्टर की तरह इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। वर्ष 2014 के अंत तक इन्हें प्रशिक्षित करके आरडीओ के रूप में प्रखंड प्रशासन की कमान सौंप दी जाएगी।

नई व्यवस्था

- वर्तमान बीडीओ को वापस कर दिया जाएगा उनकी सेवाओं में
- पहली बार बहाल हुए ग्रामीण विकास संवर्ग के पदाधिकारी

नए आरडीओ के प्रखंडों की जिम्मेदारी थामने के साथ ही पहले से बीडीओ के रूप में तैनात पदाधिकारियों की सेवा वापस कर दी जाएगी। जिस सेवा के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें उसी सेवा में लौटा दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर इस बात की भी सहमति बन रही है कि तीन साल बाद इन आरडीओ को ही बीडीओ के रूप में नामित कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रावधान में संशोधन भी किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा का कहना है कि विभाग ने आरडीओ के प्रशिक्षण की तैयारी कर ली है। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इन्हें हर तरह से तैयार किया जाएगा।

खास फायदे

पूरी तरह से प्रशिक्षित आरडीओ के प्रखंडों में आने से कल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार तेज होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन का पहले से प्रशिक्षण इन्हें होगा। इससे योजनाओं का परिणाम बेहतर मिलने की उम्मीद है। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित इन आरडीओ को ऑनलाइन सेवाओं की मॉनिटरिंग और इनके क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।